भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3196
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026

दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार

3196. श्री लालजी वर्माः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान देश भर में दूरसंचार अवसंरचना (मोबाइल टावर, 4जी/5जी नेटवर्क) के विस्तार के लिए कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई;

(ख) ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों सहित ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी का अभाव है अथवा कमजोर सिग्नल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) उक्त क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) देश के ग्रामीण एवं दूरस्थ के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न डिजिटल भारत योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 के दौरान दिनांक 28.02.2026 तक 39,050 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं तथा 24,188.49 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

(ख) से (घ) देश के ऐसे दूरस्थ एवं ग्रामीण गाँवों तथा द्वीपों, जहाँ वर्तमान में कवरेज का अभाव है, वहाँ उच्च बैंडविड्थ क्षमता वाली इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल सेवाएँ

उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) [पूर्व में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ)] से वित्तपोषण के माध्यम से अनेक कदम और परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं।

प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

(i) भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से देश के सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) तथा गाँवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लागू किया जा रहा है।फरवरी 2026 तक देश में 2,17,805 ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के अंतर्गत सेवा हेतु तैयार किया जा चुका है। जिनमें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की 809 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अनुमोदित, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के अंतर्गत भारतनेट चरण-I एवं चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क का निर्माण तथा संबंधित ग्राम पंचायतों से मांग के आधार पर शेष गैर-ग्राम पंचायत वाले गाँवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

(ii) सरकार द्वारा वित्तपोषित 4जी सैचुरेशन परियोजना तथा अन्य मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश में 24,263 मोबाइल टावरों को चालू किया जा चुका है।

(iii) चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के बीच (2312 किमी) तथा मुख्यभूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के बीच (1869 किमी) लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की कमीशनिंग की गई है। लक्षद्वीप द्वीपसमूह में 225 किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जिससे एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) तथा अन्य सेवाएँ प्रदान की जा सकें। इन ऑप्टिकल केबल परियोजनाओं से द्वीप समूहों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल सेवाओं (4जी/5जी) तथा अन्य उच्च-गति डेटा सेवाओं के तीव्र विस्तार को सुगम बनाया गया है।

*****